'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98
Date of Publication : 15.10.2015
Date of Posting on concessional rate : 2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, क्लॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42
Website : www.uditraj.com E-mail: aicscst@gmail.com

● वर्ष : 18 ● अंक 22 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 अक्टूबर, 2015

आगामी रैली से संबंधित हैंडबिल का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि प्रदेश एवं जिला इकाइयों की ओर से भी छपवाकर वितरित करें।

जय भीम !

डॉ. भीमराव अंबेडकर

जय भारत!!

डॉ. उदित राज
राष्ट्रीय अध्यक्ष

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का
अखिल भारतीय परिसंघ
के आवाहन पर

आरक्षण विरोधियों के जवाब में 10 लाख लोगों की रैली

साथियो,

आरक्षण पर जितना हमला इस समय हो रहा है, शायद पहले कभी न हुआ होगा। गुजरात में लगभग 5 लाख पटेल, जो दुनिया की अमीर जाति है, एकजुट होकर मांग किए कि आरक्षण उन्हें दिया जाए नहीं तो खत्म किया जाए। उन्हें तो मिलना नहीं है, इसका मतलब यह खत्म करने का बहाना है। विभिन्न जगहों से आवाजें आ रही हैं कि इसको आर्थिक आधार पर किया जाए। यदि दलित, आदिवासी एवं पिछड़ा समाज चुप बैठा तो वह दिन दूर नहीं कि आरक्षण खत्म ही हो जाएगा। कभी जिन्हें गलतफहमी होती थी कि सरकार में पद जो खत्म करेगा उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो वे जान लें कि एक तिहाई से ज्यादा आरक्षित पद ठेकेदारी प्रथा, क्लास 4 में भर्ती बंद एवं आउटसोर्सिंग के द्वारा खत्म हो चुके हैं। समाज इंतजार करता है कि यह लड़ाई जनप्रतिनिधि की है। कर्मचारी–अधिकारी जी भरकर कोसते हैं कि समाज की खातिर इन्हें संघर्ष करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसे कि वे स्वयं आरक्षण का लाभ न ले रहे हों। यही सवाल जन–प्रतिनिधि कर सकते हैं कि क्यों नहीं कर्मचारी–अधिकारी लड़ते और इस्तीफा देते ? जाति प्रमाण–पत्र और आरक्षण का लाभ तो दोनो लेते हैं। अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का गठन सन् 1997 में हुआ और सबसे पहले इस सोच को तोड़ने का काम हमने किया कि अधिकारी–कर्मचारी अपने अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ें, जो कि उनके वश में है। गैरों पर दबाव और मार–पीट करके काम तो नहीं लिया जा सकता। जन–प्रतिनिधि पार्टियों के आधार पर बंटे हैं और उनकी गर्दन प्रायः सवर्णों के हाथ में होती है तो ऐसे में उनसे इतनी क्या उम्मीद ? कर्मचारी–अधिकारी एवं सामाजिक व्यक्ति न तो किसी के दबाव में हैं, न नौकरी को खतरा है और न ही पार्टी के आधार पर बंटे हैं। यदि लाखों की संख्या में इकट्ठा होने लगें तो दबाव वश न केवल अपने जन–प्रतिनिधि लड़ने के लिए आगे आएंगें बल्कि सभी पार्टियां पीछे होंगीं। परिसंघ ने जब 11 दिसंबर, 2000 को राम लीला मैदान, नई दिल्ली में ऐतिहासिक रैली की तो तीन संवैधानिक संशोधन हुए थे। 5 लाख की रैली का जवाब आगामी 7 दिसंबर को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में 10 लाख से देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं दिखता।

स्थान : रामलीला मैदान, नई दिल्ली

दिनांक व समय : 7 दिसंबर, 2015 प्रात: 10 बजे

उ0प्र0 में लाखों कर्मचारियों का डिमोशन शुरू हो गया है। पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार प्रथम बार 85वां संवैधानिक संशोधन करके बचाया गया था। दूसरी बार जब पदोन्नति में आरक्षण को बचाने का मामला 2006 में सुप्रीम कोर्ट में आया तो परिसंघ के चेयरमैन, डॉ0 उदित राज ने ही सामाजिक न्याय मंत्री, कानून मंत्री एवं कार्मिक मंत्री पर दबाव बनाकर निजी वकील से पैरवी करायी। सरकार ने उनके कहने पर एडवोकेट के. पारासरन, एम. मैरियारपुत्थम एवं सुब्बा राव को पैरवी के लिए लगाया और उस समय 40 लाख रूपये का भुगतान हुआ, तब जाकर पदोन्नति में आरक्षण बचा। 4 जनवरी, 2011 को लखनऊ हाई कोर्ट ने जब पदोन्नति में आरक्षण खत्म किया तो डॉ0 उदित राज ने तीसरी बार बचाने का प्रयास किया लेकिन वहां के कर्मचारी उन्हें अछूत समझे और वे स्वयं लड़ने लगे। जब परिसंघ का साथ नहीं दिया तो क्या किया जा सकता था और अब जब डिमोशन हो रहा है तो उसके वे ही जिम्मेदार हैं। इन्होंने जन–धन का इस्तेमाल गलत दिशा में किया और संदेश गया कि हममें फूट है, जो 1997 में आरक्षण विरोधी आदेशों के विरुद्ध संघर्ष के समय नहीं था। गत् 18 साल से परिसंघ के सिवाय क्या किसी संगठन ने हंगामा करने के अलावा अधिकार बचाए और लिए हैं। लोकपाल में आरक्षण का प्रावधान परिसंघ ने बहुजन लोक पाल बिल पेश करके कराया। निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए 2004 में मंत्रियों की कमेटी, 2006 और 2008 में अधिकारियों की समिति बनी लेकिन समाज ने हमारा पूरा साथ नहीं दिया नहीं तो आज कुछ और ही स्थिति होती। कभी–कभी समाज हंगामा और जातीय भावना में ज्यादा विश्वास करता है और इस दौर में कुछ ऐसा ही हुआ है। अब लेने की बात तो क्या, जो है, वही नहीं बच पा रहा है।

तथाकथित अम्बेडकरवादी डॉ0 उदित राज को भाजपा में शामिल होने पर हमले से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए कि संसद में जितना दलितों के अधिकार और उत्पीड़पन पर उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, क्या किसी और ने किए ? वे क्यों नहीं चर्चा करते कि किसकी सरकार उ0प्र0 में थी, जब पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार छीना गया था। अब तो एक ही विकल्प है कि लाखों–लाख की संख्या में इकट्ठा होना शुरू हों तभी आरक्षण बच सकता है। आए दिन दलितों पर हमला बढ़ रहा है। उसे रोकने के लिए सशक्त बनाना होगा और वर्तमान में आरक्षण के अलावा कोई अन्य माध्यम नहीं है। क्या किसी ने रोका है कि दलित, आदिवासी, पिछड़े मीडिया, उद्योग, शेयर बाजार, उच्च शिक्षा, सेवा आदि क्षेत्रों में उपस्थिति दर्ज न करें। आरक्षण की लड़ाई लड़ने वालों को कहा जाता है कि यह तो चंद लोगों के लाभ के लिए है, अन्य क्षेत्रों में भी भागीदारी के लिए संघर्ष करना चाहिए। ऐसा कहने वाले स्वयं क्यों नहीं करते ?

देश में दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के लिए संवेदना नहीं है। इसलिए ताक़त के बल पर ही ये अपने अधिकार और सम्मान को ले सकते हैं। यदि 10 लाख लोग 7 दिसंबर, 2015 को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में इकट्ठे हो जाएं तो क्या सरकार पदोन्नति में आरक्षण पर बिल लाकर पास कराने के लिए बाध्य नहीं होगी ? आरक्षण कानून बनने से क्या रोका जा सकता है ? उच्च पदों पर भागीदारी से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता।

–: निवेदक :–

जगजीवन प्रसाद, धर्म सिंह, केदाननाथ (उ0प्र0), सिद्धार्थ भोजने, अर्चना भोयर, संजय कांबले, संजय अधांगले, सिद्धर्थ कांबले (महाराष्ट्र), महासिंह भूरानिया, एस.पी. जरावता (हरियाणा), दर्शन सिंह चंदेढ़, तरसेम सिंह (पंजाब), ब्रह्म प्रकाश, डॉ0 नाहर सिंह, रवीन्द्र सिंह, एन.डी. राम, आर.सी. मथुरिया, डॉ0 अंजू काजल, रामनंदन राम, आर.एस. हंस,कर्म सिंह कर्मा, डॉ. धनंजय (दिल्ली), मूलाराम, विश्राम मीणा, एम.एल. रासु, मुकेश मीना (राजस्थान), हरिश्चंद्र आर्या, हीरा लाल, रोहित कुमार (उत्तराखंड), मिहिर सेठी, आलेख मलिक, डी.के. बेहरा, नारायण चरनदास (उड़ीसा), परमहंस प्रसाद, बी. भारती, (मध्य प्रदेश), आर.एस. मौर्य, रामूभाई वाघेला, एन.जे. परमार, योगराज वाघेला (गुजरात), एस. करुपइया, पी.एन. पेरुमल, जी. श्रीनिवासन, एम. माठी पर्यनव (तमिलनाडु), के. रमनकुट्टी (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), के. महेश्वर राज, जे.बी. राजू (तलंगाना) डॉ0 श्याम प्रसाद (आंध्र प्रदेश), अनिल मेश्राम, हर्ष मेश्राम (छत्तीसगढ़), कमल कृष्ण मंडल, रामेश्वर राम, सपन हलदर, विश्वजीत शाह, मनमोहन बोराल (पश्चिम बंगाल),

दिल्ली में हुआ रेलवे कर्मचारियों का सम्मेलन

ऑल इंडिया एस.सी./एस.टी. रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन की नीतियों के खिलाफ बनी सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी

ऑल इंडिया रेलवे अनुसूचित जाति/जन जाति के कर्मचारियों द्वारा 27 सितंबर, 2015 को मावलंकर हॉल कांस्टीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग पर एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 18 जोन के नेता तथा अन्य कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन, डॉ0 उदित राज थे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद माननीय महेश गिरि उपस्थित थे। यह कार्यक्रम अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉ0 उदित राज और महेश गिरि एवं विभिन्न जोनों से आए हुए पदाधिकारियों ने बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर व भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित किया। नार्दर्न रेलवे से राम नंदन राम एवं रेलवे बोर्ड से श्रीमती कृष्णा कुमारी ने मंच का संचालन किया।

डॉ. उदित राज रेलवे कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए

सर्वप्रथम गाजियाबाद से आए हुए श्री भूप सिंह ने अशोक कुमार एंड कंपनी के बारे में बताते हुए कहा कि जब से ये लोग आए हैं, तब से इन्होंने ऑल इंडिया रेलवे एस.सी./एस.टी. एसोसिएशन को जेब की संस्था बना दिया है और कर्मचारियों की समस्याओं को पीछे कर दिया है।

रामनंदन राम ने मंच का संचालन करते हुए कहा कि मैं पहले रेलवे एस.सी./एस.टी. एसोसिएशन में नार्दर्न रेलवे का जोनल प्रेसीडेंट हुआ करता था और दलित कर्मचारियों के लिए हमेशा अग्रसर रहता था लेकिन अशोक कुमार एंड कंपनी जब से आए इन्होंने लोगों की समस्या न सुनते हुए हर काम के पैसे लेने शुरू कर दिए और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी इन लोगों ने लेन-देन का काम शुरू कर दिया और अपनी जेब भरनी शुरू कर दी। जिसके कारण मेरी अंतरात्मा ने इनके साथ रहने की गवाही नहीं दी और मैंने जोनल प्रेसीडेंट पद से इस्तीफा दे दिया और यही सोचकर इस्तीफा दिया कि जब 2006 में एक जनरल बॉडी बुलाई गयी थी तब इनको निष्कासित कर दिया था और इन्होंने अपनी गुंडागर्दी से अपना नाम डलवाया और लोग इनके खिलाफ भड़क उठे तो इन्होंने अपना बाइलॉज अपने तरीके से मैनुपुलेट कर लिया और इस बाइलॉज के अनुसार 50 रूपये का वार्षिक मेंबरशिप है, उसके बाद इन्होंने लोगों के बीच में बाइलॉज के विपरीत 100 रूपये की पर्चियां छपवा ली और सारे देश से 50 रूपये की बजाए 100 रूपये का सालाना प्रत्येक कर्मचारी से चंदा इकट्ठा किया जिससे इन्होंने लखनऊ में अपने 2 मकान खरीदे और दिल्ली में भी एक मकान खरीदा तो उस पैसे का इस्तेमाल केवल इन्होंने अपनी तरक्की के लिए किया। पूरे 2004 से लेकर आज तक रेलवे में पड़ी हुई खाली रिक्तियों पर न तो वैकलॉग भरने के लिए आंदोलन किया और बहुत सारे कैडर जो ठेकेदारी में चले गए न ही उनको रोकने के लिए इन्होंने आंदोलन किया। इसी तरह से जिस एसोसिएशन के ये नेता हैं, उस एसोसिएशन का अगर 25 प्रतिशत भी काम किया होता तो आज यह सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता नहीं होती।

सिद्धार्थ कांबले (मुंबई) ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस मकसद से आज यहां इकट्ठे हुए हैं, उसके बारे में बहुत जरूरी बातें बताना जरूरी है और उन्होंने कहा कि सेंट्रल एक्च्यूवि कमेटी ने चंद लोगों को चुन रखा है और जिन पर भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने समाज को धोखा दिया और बाइलॉज को भी चुनिंदा लोगों ने बदल दिया। जहां रेलवे में साढ़े तीन लाख कर्मचारी हैं तो 125 लोग उसका बाइलॉज में कैसे संशोधन कर सकते हैं। जहां आप ब्राह्मणवादी को बदनाम करते हैं तो ये लोग भी खुद उसी प्रकार से अपने लोगों के साथ व्यवहार करते हैं और अपनी मर्जी से लोगों को चुनकर जोनों में बिठा देते हैं, उसके बावजूद भी जोन के लोगों में एकता नहीं है और ब्रांच लेवल पर भी जो लोग बैठे हुए हैं, उनको भी कोई आजादी नहीं हैं, इसका मतलब केवल अशोक कुमार एंड कंपनी ने सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी को प्राइवेट कंपनी की तरह बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी को चुनने के लिए जोन से लेकर ब्रांच लेवल तक लोकतांत्रित तरीके से सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी को चुनने का अधिकार तक नहीं हैं। ये लोग अपनी मर्जी से 4-5 लोगों को चुनते हैं और उन्हें बुलाकर साइन करा लेते हैं और इनका चुनाव हो जाता है। इसका मतलब रेलवे एस.सी./एस.टी. एसोसिएशन में डेमोक्रेसी नहीं है।

धर्मेंद्र (सिकंदराबाद) ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. उदित राज जी को शेर की उपाधि देते कहा कि सच्ची ईमानदारी से डॉ. उदित राज जी के साथ राष्ट्रीय महासचिव ब्रह्म प्रकाश समाज की लड़ाई के लिए जगे हुए हैं, लेकिन समाज ही सोया हुआ है। इसलिए सभी साथियों से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अगर हम लोग एकजुट होकर भ्रष्ट लोगों को हटाने के लिए उदित राज जी के साथ खड़े होते हैं तो रेलवे से भ्रष्ट नेताओं का सफाया हो जाएगा।

रामेश्वर राम (साउथ ईस्टर्न रेलवे) ने कहा कि रेलवे में पहले जनरल यूनियन हुआ करती थी मगर उसमें एस.सी./एस.टी. कर्मचारियों की समस्याओं को सुना नहीं जाता था, इसलिए रेलवे में एस.सी./एस.टी. एसोसिएशन को बनाने की जरूरत पड़ी। लेकिन इन्हीं एसोसिएशन के नेताओं ने जनरल यूनियन को मान्यता दिलवाने के लिए पैसे लेकर अपने लोगों से जनरल यूनियन को वोटिंग करवायी। एकदिन मैं अशोक कुमार के घर पर बैठा हुआ था तब अशोक कुमार ने मुझे यह कहा कि तुम बिहार के चमार हो और मैं यू.पी. का जाटव हूं। हम दोनो भाई हैं। आप इस उदित राज के चक्कर में क्यों पड़ते हो और इनकी जाति के लिए गालियां दी तो मेरा उस दिन से अशोक कुमार से मन खट्टा हुआ और मैंने उनको यह समझाया कि डॉ0 भीमराव अम्बेडकर महार जाति से होने के बावजूद अगर वे केवल महार जाति की बात करते तो आज चमार, जाटव, बाल्मीकि, धोबी और खटीक हम कहीं भी नजर नहीं आते। क्योंकि दलितों में दलित की सभी जातियां आती हैं, इसलिए डॉ0 अम्बेडकर ने केवल दलित की लड़ाई लड़ी किसी एक जाति की लड़ाई नहीं लड़ी। उसी प्रकार डॉ0 उदित राज जी कभी भी संगठन के अंदर किसी भी प्रकार की विशेष जाति को लेकर हमला नहीं किया और डॉ0 उदित राज ने दलित को केवल दलित माना क्योंकि पूरे 18 वर्षों के अंतराल में आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए उदित राज जी ने हमेशा संघर्ष किया और आज भी डॉ0 उदित राज जिस जाति से हैं उस जाति से संगठन में उनके पास उनकी अपनी जाति का कोई पदाधिकारी तक नहीं है तो ये लोग केवल जाति की राजनीति करते हैं, जबकि आज के समय में दलित की लड़ाई लड़ने के लिए हमें जाति की बात करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि हम लोग बंटे हुए हैं, इसीलिए दूसरे लोग हम पर हावी हो रहे हैं। उन्होंने खास बात यह कही कि साउथ ईस्टर्न रेलवे में जनवरी 2008 से 6000 से ज्यादा बैकलॉग पड़े हुई हैं, लेकिन अशोक कुमार ने साउथ ईस्टर्न रेलवे की केवल 6000 खाली पदों की भर्ती के लिए कोई काम नहीं किया जिससे दलित समाज का 29 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष का नुकसान हो रहा है और साउथ ईस्टर्न रेलवे में विजय राम राय अशोक कुमार को 5 लाख रूपये सालाना का पेमेंट करता है। ऐसा लोगों का कहना है कि शायद फिर प्रत्येक जोन में इसी प्रकार होता होगा।

बी.एल. सूर्यवंशी (म.प्र.) ने कहा कि अशोक कुमार एंड कंपनी ने मुझे मारने के लिए एक लाख रूपये की सुपारी बदमाशों को दी और मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तो मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी लेकिन इनके राजनैतिक संबंधों के कारण मेरी थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई और कोर्ट से दर्ज करायी तो इन्होंने पैसा देकर पुलिस को अपने प्रभाव में लाकर थाने से रिपोर्ट नार्मल भिजवा दी। इस प्रकार अशोक एंड कंपनी के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसे जान से मारने तक पर उतारू हो जाते हैं जो नेता समाज में केवल चंदा लेने के बल पर उस पैसे का इस्तेमाल केवल अपने लोगों को डराने-धमकाने में करता हो तो वह समाज की लड़ाई कदापि नहीं लड़ सकता क्योंकि जिसके समाज के नेता ही अपने कर्मचारियों के दुश्मन बन जाएं, उसको दुश्मन पालने की आवश्यकता नहीं होती। उनको उनके रहनुमा ही मार देते हैं।

श्रीमती कृष्णा ने मंच का संचालन करते हुए बीच-बीच में अपनी बातों को रेलवे एस.सी./एस.टी. एसोसिएशन के संबंध में कहा कि मैंने कुछ बातें इन लोगों के बीच में रखी और इनके कार्यकलापों के खिलाफ चर्चा की तो इन्होंने मुझे खुद सी.ई.सी. से हटा दिया और नोटिस थमा दिया। इसी तरह अगर इस संस्था में कोई भी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है और उसे निकाल दिया जाता है। यह परंपरा ठीक नहीं है क्योंकि अपनी बात तो दूसरे लोग सुनते ही नहीं हैं अगर एसोसिएशन के लीडर भी अनसुना करेंगें और उनकी बातों को दबाएंगें तो फिर हम जाएं कहां ?

भूपेन्द्र सिंह, मुकेश मीना , विश्वजीत शाह , श्रीधरन, सुशांत सांत्रो, रामेश्वर प्रसाद, जसवंत सिंह, एस.पी. तांते, एच. सी. भगत, पूरनचंद सोंगरा, आदेश कुमार, चन्नप्पा आदि ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।

सांसद, श्री महेश गिरि ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भेदभाव संगठन में हो या प्रशासन में हो वह ठीक नहीं है, क्योंकि अगर संगठन में ही भेदभाव होगा और उन्हें अनदेखा किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि लोग उसके खिलाफ आवाज उठाएंगें और अगर इस प्रकार के लोग संगठन में बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को हटाने के लिए मैं, डॉ0 उदित राज, सांसद महोदय के साथ रेल मंत्रालय और सरकार से बात करने के लिए तैयार हूं। जहां-जहां मुझे उदित राज जी बुलाएंगें किसी भी जगह संघर्ष करने की आवश्यकता होगी तो मैं डॉ0 उदित राज जी के साथ उनके कदम से कदम मिलाकर दलित उत्पीड़न को खत्म करने के लिए हमेशा साथ रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि समाज को डॉ0 उदित राज जैसा नेता मिला है तो समस्त रेलवे कर्मचारियों को डॉ0 उदित राज जी का धन्यवाद देना चाहिए कि आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हर प्रयास करने को तैयार हैं।

परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव, ब्रह्म प्रकाश जी ने बाहर से आए हुए सभी रेलवे कर्मचारियों और नेतागणों का हार्दिक स्वागत करते हुए प्रस्ताव रखा कि अब यह लड़ाई अंत तक होगी जब तक कि भ्रष्ट लोगों को नहीं निकाला जाएगा। मगर उसके लिए आप सभी लोगों को एक साथ रहकर सेंट्रल एक्जीक्यूटिव के खिलाफ लिखकर देना होगा कि इस एसोसिएशन में दलित की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। आज आरक्षण पूरे देश में सिकुड़ता जा रहा है और कोई भी संगठन परिसंघ के अलावा इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा है जबकि भारत में दलित कर्मचारियों की संख्या केवल रेलवे में एक चौथाई हिस्सा है। अगर रेलवे कर्मचारी साढ़े तीन लाख में से

पृष्ठ शेष 3 पर

मुंबई में आरक्षण बचाओ परिषद सम्पन्न

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से 10 अक्टूबर, 2015 को डॉ0 अम्बेडकर भवन, दादर (पूर्व) में आरक्षण बचाओ परिषद का आयोजन किया गया। परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 उदित राज ने प्रमुख मार्गदर्शक की भूमिका में परिषद को संबोधित किया। परिसंघ के मुंबई अध्यक्ष, डॉ0 संजय कांबले बापेरकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस परिषद में अखिल भारतीय ओबीसी महिला फेडरेशन की भाग्यलक्ष्मी, महाराष्ट्र अध्यक्ष – सिद्धार्थ भोजने, रेल यूनियन के सिद्धार्थ कांबले, मेट्रोलोजी डिपार्टमेंट के संजय अधांगले ने अपने विचार प्रस्तुत किये। परिषद का संचालन आयु. प्रमोद कांबले ने किया।

आरक्षण बचाओ परिषद के अवसर पर मुंबई पहुंचने पर डॉ. उदित राज जी का स्वागत करते हुए मुंबई परिसंघ के पदाधिकारीगण

परिषद को संबोधित करते हुए डॉ0 उदित राज जी ने 18 सालों से किए हुए कार्य का संक्षिप्त विवेचन किया। जिसमें 1997 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए 5 आरक्षण विरोधी आदेशों की वापिसी और उसके संघर्ष के बारे में बातया। उन्होंने बताया कि तत्कालीन वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में 85वां संवैधानिक संशोधन बिल पास करके पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके पहले सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए भाजपा सहित अन्य पार्टियों के सांसदों से बात करके मार्च 1999 में 2 बार पार्लियामेंट का कामकाज बंद करवाया लेकिन तत्कालीन सरकार ने नजरंदाज किया।

2006 में उच्च शिक्षा क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण दिलवाया, जिसे न्यायालय में चुनौती दी गयी मगर ओबीसी नेताओं ने लड़ने के लिए मना कर दिया।

संविधान को कमजोर करने वाले अन्ना हजारे द्वारा प्रस्तुत लोकपाल बिल का विरोध करके बहुजन लोकपाल बिल तैयार करके उसमें आरक्षण का प्रावधान करवाया। आरक्षण की लड़ाई के लिए मैंने आई.आर.एस. का इस्तीफा देकर राजनैतिक पार्टी तैयार की मगर पर्याप्त सपोर्ट न मिलने के कारण भाजपा में शामिल हुआ।

आरक्षण के बारे में लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है। जैसे कि आरक्षण से कुछ चंद लोगों को ही लाभ मिला है। असल में पिछड़े हुए आज भी पिछड़े ही हैं। यह कहकर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। आरक्षण की लड़ाई कर्मचारी / अधिकारी जैसे बुद्धिजीवी लोगों को ही लड़नी चाहिए। सिर्फ राजनैतिक नेताओं पर निर्भर न रहे। क्योंकि ये लड़ाई लड़ने वालों को कभी-कभी उनकी राजनैतिक पार्टी घर का रास्ता दिखाती है।

सावधानी न बरतने के कारण करीब 1/3 आरक्षण समाप्त हो चुका है। निजीकरण, ठेकेदारी प्रथा, आउट सोर्सिंग आदि द्वारा आरक्षण समाप्त किया गया है। आरक्षण की लड़ाई में अन्य जाति समूह का पर्याप्त मात्रा में सहयोग नहीं मिल रहा है। मीडिया भी सपोर्ट नहीं कर रही है। उ0प्र0 सरकार द्वारा सावधानी न बरतने के कारण वहां के करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों/अधिकारियों पर डिमोशन की नौबत आ चुकी है। हार्दिक पटेल द्वारा गुजरात में चल रहे आंदोलन के पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। पटेल समाज को आरक्षण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि पटेल सामाज राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार/उद्योग क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में कार्यरत है। एक-एक पटेल कई लोगों को रोजगार देने में सक्षम हैं।

आर.एस.एस. के हाइटेक, संगठित तथा पूर्व नियोजित प्रचार के फलस्वरूप बीजेपी सत्ता हासिल करने में सफल हुई है। यह उदाहरण सामने रखकर हमें भी हाइटेक, संगठित प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर छात्र संगठन की स्थापना करके युवकों के लिए सशक्त प्लेटफार्म निर्माण करने की आवश्यकता है। जिससे अपने आंदोलन के लिए काबिल युवा कार्यकर्त्ता उपलब्ध हो जाएंगें।

निजी सेक्टर में आरक्षण की हमारी मांग बैकफुट पर है, क्योंकि हमें सरकारी क्षेत्र में जारी आरक्षण बचाने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है। आरक्षण विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए 7 दिसंबर, 2015 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया हैं, उसमें महाराष्ट्र से ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने का आवाहन डॉ0 उदित राज जी ने किया।

– संजय कावले
अध्यक्ष, मुंबई परिसंघ
9820111665

+++

दिल्ली में हुआ रेलवे कर्मचारियों ...

शेष 2 का

ढाई-तीन लाख कर्मचारी अपने दलित समाज के आरक्षण पर कुठाराघात के खिलाफ अगर नहीं उतरा तो वह दिन दूर नहीं जब आरक्षण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हर विभाग में दलित कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं और उनके स्थानों पर ठेकेदारी प्रथा के अनुसार गैर दलित कर्मचारियों को लिया जाता है। क्योंकि ठेकेदारी प्रथा में आरक्षण नहीं है। इसलिए बैकलॉग पर भर्ती नहीं होती जिसका फायदा सामान्य वर्ग को होता है। केवल सफाई कर्मचारी में पूर्ण रूप से केवल दलित कर्मचारी ही लिए जाते हैं। उनको सरकारी दैनिक वेतन के अनुसार भी उन्हें वेतन और सुविधाएं नहीं मिलती हैं, इसलिए आज पूरे देश के रेलवे कर्मचारी नेताओं से अनुरोध करते हुए कहा कि देश में आरक्षण की लड़ाई को लड़ने के लिए रेलवे कर्मचारियों को भी विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के साथ उतरना पड़ेगा, क्योंकि अगर रेलवे भी धीरे-धीरे करके ठेकेदारी प्रथा में चला गया तो फिर दलित समाज का क्या होगा, यह सोचकर देखें। मगर अशोक कुमार एंड कंपनी ने समाज की चिंता नहीं की। आरक्षण को बचाने के लिए चिंता नहीं की। लोगों की आवाज को दबाने की चिंता की और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की चिंता की। इसलिए आप सभी लोगों को यहां पर आमंत्रित किया गया है कि अब समय आ गया गया कि गलत लोगों को बाहर निकालो, सही लोगों को चुनो और पूरे देश में आरक्षण की लड़ाई को बचाने के लिए मैदान में आओ। माननीय रेलमंत्री जी को सम्मेलन में उपस्थित सभी लोगों के हस्ताक्षर युक्त मेमोरेंडम सौंपा गया। (मेमोरेंडम वॉयस ऑफ बुद्धा के पिछले अंक में छापा जा चुका है।)

मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए डॉ0 उदित राज जी ने कहा कि अशोक कुमार एंड कंपनी के बारे में ये लोग मेरे पास पिछले वर्ष अपने आपको बचाने के लिए आए थे और मुझसे विनती की थी कि हमें आप बचा लें। हम दलित आंदोलन को आपके साथ मिलकर लड़ेंगें। इसलिए मैंने इनको शरण दी। लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आए और फिर इन्होंने वही करना शुरु कर दिया जो ये करते चले आए हैं। आज ये लोग संगठन में हों या बाहर हों कहीं भी दलित आवाज को नहीं उठाते हैं और जब जिसकी सरकार आती है, उसी के पांव पकड़ लेते हैं, सिर्फ अपने आपको बचाने के लिए लेकिन हमने इनको पिछली रैली के बाद पूरे 9-10 महीने आजमाया। आज जरूरत है कि अपने स्वार्थ को त्यागकर हार्दिक पटेल जैसे नौसिखिए को पता नहीं कि आरक्षण का नियम क्या है और आरक्षण क्यों दिया जाता है, उसको इसकी ए.बी.सी.डी, नहीं पता और हार्दिक पटेल को आगे करके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं और वे इसलिए करते हैं क्योंकि आज देश में हजारों संगठन हैं। वे केवल बाबा साहेब की जयंती हो या 6 दिसंबर का परिनिर्वाण-दिवस हो या दफ्तरों में अपना ट्रांस्फर-पोस्टिंग बचानी हो सिर्फ वहीं दिखाई देते हैं और केवल नेताओं को कोसते हैं। मैं जब से पार्लियामेंट गया हूं, तबसे मैंने 35 बार दलित मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट में सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि मैं गया इसीलिए हूं कि पार्लियामेंट में जाकर दलितों के मुद्दों को वहां उठा सकूं। क्योंकि मैंने देखा था कि जब मैं सांसद नहीं था तो मैंने लाखों लोगों को एकत्रित करके रैलियां की लेकिन संसद भवन के अंदर किसी ने उस बात को नहीं उठाया और हमारे संगठन ने आरक्षण बिल को लेकर संशोधन भी करवाए। लोक पाल बिल में संशोधन कराते हुए आरक्षण का प्रावधान भी कराया और ऐसे सैकड़ों मामलों पर आंदोलन करते हुए अधिकार सुनिश्चित कराए लेकिन कुछ लोग राजनीति करके पार्टियों के माध्यम से संसद या विधान सभाओं में पहुंच तो जाते हैं लेकिन वे अपने समाज की बात को कह नहीं पाते क्योंकि समाज की बात जो करते हैं तो उनको पार्टियां निकालकर बाहर खड़ा कर देती हैं और बाद में नहीं पूछती। ऐसे अनगिनत नेताओं के उदारण बड़ी-बड़ी पार्टियों में हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी सांसदी की परवाह नहीं की है। मैं संसद भवन के अंदर और मंत्रालयों में अपनी बात कहने से नहीं चूंका हूं। इसके बावजूद भी हमारे कुछ नेता दलितों में भी उपजाति की राजनीति करते हैं और हमारे ऊपर सवाल खड़ा करते हुए मुझसे इस्तीफा मांगते हैं। क्या केवल डॉ0 उदित राज ही बार-बार इस्तीफा देगें, क्योंकि एक बार अपनी कमिश्नरी से इस्तीफा दिया और संसद में पहुंचा हूं तो अब हमारे अपने दलित समाज के नेता जो कुछ नहीं करते, जाति की रानजीति करते हैं और समाज को ठगते हैं, वे सांसदी का इस्तीफा मांग रहे हैं तो क्या वे किसी पद से इस्तीफा दिए हैं या अपने स्वार्थ को त्यागा है, इतने आंदोलन किए हैं? यह सरासर बेईमानी है कि जो ज्यादा काम करता है, उसी से ही लोग हिसाब-किताब मांगते हैं? क्या कभी उन नेताओं से भी हिसाब मांगा जाता है जो समाज के रिजर्वेशन के माध्यम से आई.ए.एस. बने, मंत्री बने, विधायक या सांसद बने। अगर यह समाज मुझे या परिसंघ के माध्यम से दलित आंदोलन को राहत दी होती और उपजाति की लड़ाई छोड़कर एक साथ लड़ाई लड़ी होती तो आरक्षण के खिलाफ जो आज आवाज उठ रही है, वह आवाज आज नहीं उठ रही होती। यह अनुग्रह करते हुए कहा कि आज अगर नहीं जागे तो कल पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए सर्वदलित समाज को आवाहन किया कि रेलवे में साढ़े तीन लाख कर्मचारी हैं और गैर रेलवे में लाखों कर्मचारी हैं। अगर इनमें से 50 प्रतिशत भी कर्मचारी-अधिकारी 8 नवंबर को लखनऊ की रैली और 7 दिसंबर को दिल्ली की रैली में हार्दिक पटेल का जवाब 10 से 15 लाख लोगों की भीड़ से नहीं दिया तो बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका है। इसलिए जितने रेलवे ऐसोसिएशन के लोग यहां आए हुए हैं, अगर एक-एक नेता एक-एक हजार कर्मचारियों के नाम और नंबर लिखकर देगें तो दो-ढाई लाख कर्मचारियों के नंबर एकत्रित हो सकते हैं, जिनसे हम संवाद कर सकें और उन्हें उनकी ताक़त का एहसास कराया जा सके। इसके साथ रेलवे के नेताओं से कहा कि आप लोग जब आज भ्रष्ट लोगों के खिलाफ एकत्रित हुए हैं तो यह जीत अवश्यक होगी, इसके लिए चाहे जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े हम आपके साथ हैं। इन भ्रष्ट लोगों से लड़ने के लिए सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी बनाने का आवाहन किया और करीब 50 लोगों की सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी बनी।

सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी में रामनंदन राम, जसवंत सिंह, अनिल कुमार, ओ.पी. मीना, श्रीमती कृष्णा, सिद्धार्थ कांबले, श्रीधरन, रामेश्वर राम, बी.एल. सूर्यवंशी, पी.धर्मेंद्र, राजेश नायक, मुकेश मीना, भीषम सिंह, एच. सी. भगत, भूपेन्द्र सिंह, पूरनचंद सोंगरा, भगवंत सिंह, राधाकृष्ण बकोरिया, रतनचंद्र दास, विश्वजीत शाह, टी. प्रभुचरन, एम.जे. सुधाकर, जी. अचीनेशन, जी. नटराज, ए.एस. श्री नुवासन, सी.पी. सिंह, रामेश्वर राम, डी.डी. मालाजपुरे, एस.पी. तांते, एम. एम बरल, मनीच बोलदर, एस.एल. संकी, भीषम पाल सिंह, आदेश कुमार, भूदेव प्रसाद, रवीन्द्र सागर, चन्नप्पा, सुनील कोइले, राजेन्द्र बाबू विनय हेम्ब्रोम, रामेश्वर प्रसाद, सुसांत सांत्रो, मुकेश मीना चुने गए।

– बह्म प्रकाश
राष्ट्रीय महासचिव
मो. 9871170028

+++

आगामी रैली से संबंधित पोस्टर का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि प्रदेश एवं जिला इकाइयों की ओर से भी छपवाकर वितरित करें।

जय भीम ! जय भारत !!

अनुसूचित जाति / जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय

परिसंघ

के आवाहन पर

डॉ० उदित राज
(पूर्व आई. आर. एस.)
राष्ट्रीय चेयरमैन

आरक्षण विरोधियों के जवाब में

10 लाख लोगों की रैली

07 दिसंबर, 2015 (सोमवार) को प्रात: 10 बजे रामलीला मैदान, नई दिल्ली पर

भारी संख्या में पहुंचकर रैली को सफल बनाएं

मुख्य मांगें

1. पदोन्नति में आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पास करवाना 2. आरक्षण कानून बनाओ 3. निजी क्षेत्र एवं न्यायपालिका में आरक्षण 4. सफाई काम में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना 5. खाली पदों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान 6. समान शिक्षा 7. भूमिहीनों को भूमि 8. अनुसूचित जाति योजना एवं जन जाति उप योजना कानून बनाओ 9. एक राज्य का जाति प्रमाण-पत्र सभी राज्यों में मान्य हो 10. महंगाई की दर से छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी

निवेदक :- जगजीवन प्रसाद, धर्म सिंह, केदाननाथ (उ.प्र.), सिद्धार्थ भोजने, अर्चना भोयर, संजय कांबले, संजय अधांगले, सिद्धर्थ कांबले (महाराष्ट्र), महासिंह भूरानिया, एस.पी. जरावता (हरियाणा), दर्शन सिंह चंदेढ़, तरसेम सिंह (पंजाब), ब्रह्म प्रकाश, डॉ. नाहर सिंह, रवीन्द्र सिंह, एन.डी. राम, आर.सी. मथुरिया, डॉ. अंजू काजल, रामनंदन राम, आर.एस. हंस, कर्म सिंह कर्मा, डॉ. धनंजय (दिल्ली), मूलाराम, विश्राम मीणा, एम.एल. रासु, मुकेश मीना (राजस्थान), हरिश्चंद्र आर्या, हीरा लाल, रोहित कुमार (उत्तराखंड), मिहिर सेठी, आलेख मलिक, डी.के. बेहरा, नारायण चरनदास (उड़ीसा), परमहंस प्रसाद, बी. भारती, (मध्य प्रदेश), आर.एस. मौर्य, रामूभाई वाघेला, एन.जे. परमार, योगराज वाघेला (गुजरात), एस. करुपइया, पी.एन. पेरुमल, जी. श्रीनिवासन, एम. माठी पर्यनव (तमिलनाडु), के. रमनकुट्टी (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), के. महेश्वर राज, जे.बी. राजू (तेलंगाना) डॉ. श्याम प्रसाद (आंध्र प्रदेश), अनिल मेश्राम, हर्ष मेश्राम (छत्तीसगढ़), कमल कृष्ण मंडल, रामेश्वर राम, सपन हलदर, विश्वजीत शाह, मनमोहन बोराल (पश्चिम बंगाल), मधुसूदन कुमार, विनय मुंडू, (झारखंड), आर.के. कलसोत्रा (जे एंड के), मदन राम, कुमार धीरेन्द्र, शिवधन पासवान (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, पुरुषोत्तम दास, चन्नप्पा (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.)

पत्राचार : टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-1, फोन : 23354841-42, टेलीफैक्स : 23354843
Email : parisangh1997@gmail.com www.uditraj.com Whatsapp : 9999504477

Sample of the Poster for the forthcoming Rally is being published. It is an earnest appeal to the Confederation Leaders that they should get it print on behalf of State and District Units and distribute

Jai Bheem !

Jai Bharat !!

All India Confederation of SC/ST Organisations Calls

Dr. Udit Raj (Ex. I.R.S.)
National Chairman

A Rally of 10 Lakhs

To Oppose Anti-Reservationists

On 07th Dec., 2015 (Monday) at 10 AM
At Ramlila Maidan, New Delhi

Participate in large numbers to make Rally a grand success

DEMANDS

1. Pass Constitutional Amendment to provide Reservation in Promotion 2. Enact Reservation Act 3. Reservation in Private Sector and Judiciary 4. Ban contract system in Safai Work 5. Fill up backlog posts by special drive 6. Right to Equal Education 7. Land to the Landless 8. Legislation of SCP & TSP 9. Caste certificate of one State should be valid in other States 10. Raise scholarship amount as per price index.

By

Jagjiwan Prasad, Dharam Singh, Kidarnath (UP), Siddhartha Bhajane, Archana Bhoyar, Sanjay Kamble, Sanjay Adhangale, Siddhartha Kamble (Maharashtra), Mahasingh Bhurania, S. P. Jarawata (Haryana), Dharshan Singh Chanded, Tarsem Singh (Punjab), Brahm Prakash, Dr. Nahar Singh, Ravindra Singh, N. D. Ram, R. C. Mathuriya, Dr. Anju Kajal, Ramnandan Ram, R. S. Hans, Karm Singh Karma, Dr. Dhananjay (Delhi), Moolaram, Vishram Meena, M.L. Rasu, Mukesh Meena (Rajasthan), Harishchand Arya, Heera Lal, Rohit Kumar, (U.K.), Mihir Sethi, Alekh Malik, D. K. Behera, Narayan Charan Das (Orissa), Param Hans Prasad, B. Bharati (M.P.), R. S. Maurya, Ramubhai Vaghela, N.J. Parmar, Yograj Vaghela (Gujarat), S. Karuppaiah, P. N. Perumal, G. Sriniwasan, M. Mathiparayanav (Tamilnadu), K. Ramankutty (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), K. Maheshwar Raj, K. B. Raju (Telangana), Dr. Shyam Prasad (A.P.), Anil Meshram, Harsh Meshram (Chhattisgarh), Kamal Krishna Mandal, Rameshwar Ram, Sapan Haldar, Vishwajit Shah, Manmohan Boral (W. Bengal), Madhusudan Kumar, Vinay Mundu (Jharkhand), R. K. Kalsotra (J & K), Madan Ram, Kumar Dhirendra, Shivdhan Paswan (Bihar), J. Shriniwaslu, Purushottam Das, Channappa (Karnataka), Sitaram Bansal (H.P.)

Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-1, Tel : 23354841-42
Email : parisangh1997@gmail.com www.uditraj.com, Whatsapp No. 9999504477

आरक्षण - गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी का साधन नहीं

डॉ. उदित राज
संसद सदस्य (लोक सभा)
राष्ट्रीय चेयरमैन,
अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों
का अखिल भारतीय परिसंघ

आरक्षण को लोग रोजगार उन्मूलन का हथियार समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सभी सरकारें पूरे साल सैकड़ों योजनाएं चलाकर गरीबी उन्मूलन और रोजगार के लिए सतत् प्रयत्न करती रहती हैं। सरकार में नौकरियां जितनी हैं उससे 5 प्रतिशत् भी बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। आरक्षण मूल रूप से प्रतिनिधित्व के उद्देश्य की पूर्ति करता है। समय-समय पर विवाद पैदा होता रहता है कि आरक्षण सामाजिक आधार पर हो या आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार के पक्ष में तर्क देने वाले सोचते हैं कि आरक्षण गरीबी और बेरोजगारी दूर करने का हथियार है, जो कि एक भ्रम है। कुछ लोग राजनैतिक हथियार के रूप में इसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे जाति को इकट्ठा करना आसान हो जाता है। जो बेरोजगार हैं, उन्हें लगता है कि आरक्षण की वजह से ऐसी स्थिति में हैं। जातीय पूर्वाग्रह तो एक कारण है ही। अगर समाज और देश हित में आरक्षण नहीं है तो खत्म हो जाना चाहिए, यदि है तो विवाद किस बात का ?

आज़ाद भारत के पहले परिस्थितियां भिन्न रहीं। बहुतों की चिंता राजनैतिक आज़ादी की रही तो कुछ की चिंता समाज में मान-सम्मान की रही है। देश में तमाम ऐसी सोच रखने वालों में से एक डॉ0 अम्बेडकर भी रहे। उन्हें तथा उनके समर्थकों को लगा कि आज़ाद भारत में हमारी दशा क्या होगी। उस समय शासक अंग्रेज थे, जातीय भेदभाव और सोच से वे परिचित नहीं थे। उस समय दलितों और आदिवासियों की भागीदारी हर क्षेत्र में नगण्य थी। जब साइमन कमीशन भारत की समस्याओं के ऊपर अध्ययन करने आया तो यहां के दलितों को मौका मिला कि वे अपनी बात को रख सकें। परिणाम यह हुआ कि लंदन की गोलमेज सभा में बात उठी और 1932 में गांधीजी और बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का सोचना है कि इससे हिन्दू समाज की एकता बरकरार रह सकी वरना टूट भी सकती थी, क्योंकि दलितों को पृथक मताधिकार का अधिकार बर्तानी हुकूमत ने मंजूर कर ली थी।

शासन-प्रशासन में दलितों व आदिवासियों का आरक्षण इसके पहले कभी नहीं था, आरक्षण विरोधी बताएं कि तब देश गुलाम क्यों हुआ ? क्या यह कारण नहीं रहा होगा कि देश इसकी वजह से भी गुलाम हुआ होगा। इतनी बड़ी आबादी को अलग-थलग रखकर दुश्मन का मुकाबला कठिन तो था ही, कृषि, उद्योग एवं कारोबार पर भी असर पड़ा। जब इनके पास क्रय-शक्ति नहीं थी तो अर्थव्यवस्था का तो कमजोर होना ही था। समाज में खटास की वजह से सुख-शांति पर असर तो पड़ना अनिवार्य था। यदि भागीदारी हुई होती तो ये अप्रत्याशित बुकसान समाज का न हुआ होता। आरक्षण के बाद और पहले के भारत की तुलना की जाए तो पता लगेगा कि बाद वाला कहीं बहुत अच्छा है और उसमें आरक्षण का योगदान बहुत है। आरक्षण की वजह से जिनकी समाजिक-आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, उनका योगदान उत्पादन एवं शासन-प्रशासन में हुआ। कपड़ा, खाना और तमाम उपभोग की वस्तुओं की क्रय-शक्ति बढ़ी और इसका असर औद्योगिक उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर पड़ा। दलितों और पिछड़ों में राष्ट्रीयता का बोध हुआ। जब ये केवल मजदूर और अछूत थे तो वैसी स्थिति में राष्ट्रबोध का ज्ञान कैसे होता ?यहां वह चौपाई बहुत संदर्भिक है - ''कोउ नृप होई हमहि का हानी , चेरि छाणि अब होब का रानी।'' इसका मतलब है कि राजा कोई भी हो, वंचित को क्या फर्क पड़ता है।

जो लोग योग्यता और दक्षता की बात करते हैं तो उन्हें हाल में हुए व्यापक अध्ययन के निष्कर्ष को जान लेना चाहिए। अश्विनी देशपांडे, प्रोफेसर - दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स एवं थामस विसकोफ, प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) - मिसिगन विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति एवं जन जातियों को आरक्षण देने के कारण भारतीय रेलवे में 1980 एवं 2002 की अवधि का अध्ययन किया, जिसकी रिपोर्ट 'वर्ल्ड डेवलपमेंट जोर्नल' में छपी। भारतीय रेलवे पूरे विश्व में सबसे बड़ा नियोजक (नौकरी देने वाला) है, जहां पर आरक्षण लागू है। रेलवे में ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक में मिलाकर लगभग 13 से 14 लाख लोग काम करते हैं। 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों एवं 7.5 प्रतिशत जन जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसके अलावा पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण लागू है। इस अध्ययन ने पाया कि ग्रुप ए एवं बी के अधिकारी आरक्षण के कारण ही इन पदों पर पहुंच सकें हैं। प्रो0 देशपांडे एवं प्रो0 विसकोफ ने उन जोनों की तुलना की जिनमें ज्यादा दलित कर्मचारी अधिक कार्यरत् थे और जिनमें कम कार्यरत् थे। उन्होंने पाया कि दोनो जोनों में कार्यक्षमता और उत्पादकता में कोई अंतर नहीं है, उल्टे उन्होंने पाया कि कुछ जोन जिनमें दलित कर्मचारी ज्यादा थे, वहां ज्यादा उत्पादकता हुई है।

आरक्षण के बावजूद प्रमुख स्थानों पर अनारक्षित वर्ग के ही लोग बैठे हैं। लगभग सभी विश्वविद्यालय, आईआईटी एवं उच्च संस्थानों में प्रोफेसर या अहम पोस्ट पर अनारक्षित लोग ही बैठे हैं, तो हमारे देश में शोध और तकनीकी विकास क्यों नहीं हो पाया ? हाल में अमरीका के चार राज्यों का दौरा किया और सैकड़ों भारतीय डॉक्टरों से मुलाकात हुई। चर्चा के उपरांत बात उभरकर आयी कि भारत में एक भी जेनेरिक दवा की खोज नहीं हुई है। क्या इसके लिए आरक्षण जिम्मेदार है ? सेंटर ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की ओर से जारी 1,000 शीर्ष यूनिवर्सिटी की सूची में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लगातार तीसरे साल पहले पायदान पर रखा गया है। भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी शीर्ष 300 में भी शामिल नहीं है। आई.आई.टी. संस्थानों के पास तो सुविधाएं एवं पैसे की कमी नहीं है, तो फिर क्यों नहीं एक भी मौलिक रिसर्च कर पाए ?उच्च न्यायपालिका में दलित व पिछड़े तो नहीं के बराबर हैं, फिर क्यों मुकदमें के फैसले में विलंब और बार-बार भ्रष्टाचार की बात उठती है। हाल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में 50 प्रतिशत जज भ्रष्ट हैं। यही बात वरिष्ठ अधिवक्ता शांतिभूषण भी कह चुके हैं । दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाह ने कहा कि 94 प्रतिशत मृत्यु दंड दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों को ही दिया जाता है। भारत सरकार में लगभग 150 सचिव हैं - एक या दो को छोड़कर सारे अनारक्षित वर्ग से हैं तो क्यों विभागों में शिथिलता, भ्रष्टाचार और पक्षपात है ? क्या इन सब चीजों के लिए आरक्षण जितम्मेदार है ?

जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उनको भी इसका परोक्ष लाभ मिल रहा है। ज्यादातर शिक्षण संस्थाएं, उद्योग, कारोबार तथाकथित सवर्णों के लिए आरक्षित वर्ग के लोग इनका उपभोग करके किसका मुनाफा बढ़ाते हैं ? तमाम सवर्णों की शिक्षण संस्थाएं आरक्षित वर्ग के छात्रों से चलती हैं, क्योंकि ये सीट भरने में सहयोगी तो होते हैं, साथ-साथ जो छात्रवृत्ति सरकार से मिलती है, सीधे इनका फायदा होता है। जब तक मंडल लागू नहीं हुआ तब तक 10 से 15 प्रतिशत तक ही सीटों पर आरक्षित वर्ग के लोग थे। तब सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार व विलंबता की नींव क्यों पड़ी ?जिन्हें आरक्षण दिया है, वे देशवासी हैं, शत्रु नहीं, तो यह विरोध क्यों ?गुजरात में पटेल समाज के जो नवजवान आंदोलन कर रहे हैं, उनका आक्रोश है कि अपनी ही जाति के उन्नति किए लोगों से वे पीछे रह गए हैं। दुनिया की कोई भी जाति हो उसमें शत्प्रतिशत् मालामाल नहीं होते। दूसरा कारण कि सरकारी नौकरी का आकर्षण। यदि आरक्षण समाप्त भी कर दिया जाए तो अनारक्षित वर्ग के लोगों की 5 प्रतिशत भी बेरोजगारी दूर नहीं हो सकेगी। भारत सरकार की सेवाओं एवं भर्तियों की मुख्य एजेंसी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार साल में लगभग 25 प्रतिशत की भर्ती करती है और इस तरह से देश की अन्य एजेंसियों के भी आकड़े इकट्ठे कर लिए जाएं तो ज्यादा से ज्यादा दो-तीन या अधिकतक 4 लाख हो सकते हैं। यदि मान लिया जाए कि इसमें से आधी भी नौकरियां आरक्षित वर्ग को दे दी जाएं तो कितना बचता है, जिससे सवर्णों की बेरोजगारी दूर हो जाएगी ?शायद 5 प्रतिशत को भी न तो रोजगार और न ही शिक्षण संस्थानों में प्रवेश मिल पाएगा। इस तरह से आरक्षण विरोधी आंदोलन समाज और देश विरोधी है। किसी भी दृष्टि से मूल्यांकन कर लिया जाए तो पाया जाएगा कि आरक्षण से देश और समाज का लाभ ही लाभ है, बुकसान किसी तरह से नहीं है।

+++

दनकौर के पीड़ितों को अतिशीघ्र न्याय मिले और दोषी दबंगों व पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही : डॉ0 उदित राज

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2015.

डॉ0 उदित राज, सांसद एवं राष्ट्रीय चेयरमैन, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ने ग्रेटर नोएडा के दनकौर में हुए दलित उत्पीड़न की कड़ी निंदा की है और दोषी दबंगों व पुलिस वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने बताया कि लूट के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे परिवार को जब पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो उन्होंने विरोध किया। पुलिस ने जोर-जबरदस्ती की तो वे विरोध करते हुए अपने कपड़े उतारने पर मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि दबंग लोगों ने जब घर की महिलाओं के साथ बदतमीजी की और उनके कपड़े उतार दिए तब तो दबंगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई लेकिन मजबूर होकर विरोध करते हुए जब दलितों ने कपड़े उतार दिए तो उन पर अश्लीलता का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कर दिया गया।

सूचना के मुताबिक जिला गौतमबुद्ध नगर के अट्टा गुजरान गांव के रहने वाले सुनील गौतम और उसके परिवार ने यह कदम दबंगों से परेशान होकर उठाया। उसका जमीन को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा है। सुनील गौतम का आरोप है कि गांव के तीन दबंग युवकों ने तमंचे के बल पर उससे नकदी, मोबाइल और थ्रीव्हीलर की चाबी छीन ली साथ ही दबंगों ने उसकी पत्नी और दो भाभियों के साथ बदसलूकी की। जबरन उनके कपड़े भी उतार दिए। सुनील गौतम ने इसी बात की शिकायत दनकौर थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो सुनील अपने पूरे परिवार समेत आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 8 अक्टूबर को दनकौर में ही धरने पर बैठ गया। जब पुलिस उन्हें वहां से जबरन हटाने लगी तो सुनील और उसके परिवार वालों ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। पुलिस ने सुनील उसकी पत्नी, दो भाभियों और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

डॉ0 उदित राज जी ने कहा कि अतिशीघ्र दबंगों व दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले।

- सी.एल. मौर्य
निजी सचिव

+++

आरक्षण बचाने के लिए अधिक से अधिक लोगों के नाम और मोबाइल नंम्बर भेजें

7 दिसंबर, 2015 को दिल्ली की रैली हेतु मैं कई बार आप लोगों से आडियो काफ्रेंस और वॉयस कॉल द्वारा संवाद कर चुका हूं। एस.एम.एस. तो भेजा ही जा रहा है। अभी तक अपेक्षित नाम और मोबाइल नंबर हमारे पास नहीं आ पाए हैं। अधिक से अधिक नाम और नंबर भेजें ताकि उनसे संवाद किया जा सके। यदि संभव हो तो कम्प्यूटर से एक कॉलम में नाम और दूसरे कॉलम में मोबाइल नम्बर टाइप करवाकर parisangh1997@gmail. पर ईमेल कर दें। ईमेल करने में असमर्थ हैं तो अन्य माध्यमों से भी भेज सकते हैं। जो पदाधिकारी हैं या सामाजिक कार्यों में रूचि रखते हैं और अधिक सक्रिय हैं, उनका नंबर अलग से भेजें और आम लोगों के नंबर अलग से। जो अधिक सक्रिय लोग हैं, उनसे मैं व्यक्तिगत् रूप से चर्चा करूंगा।

चारों तरफ से आरक्षण खत्म करने की आवाजें उठने लगी हैं। यदि हम 10–15 लाख नाम और मोबाइल नंबर भी अपने साथियों का नहीं इकट्ठा कर पाते तो इसमें आरक्षण विरोधियों का तो कोई दोष नहीं। आप सभी से अपील है कि अतिशीघ्र अधिक से अधिक लोगों के नाम और मोबइल नंबर भेजें।

– डॉ. उदित राज
राष्ट्रीय चेयरमैन
9013869539, 9013869549

8 नवंबर को लखनऊ में पदोन्नति में आरक्षण हेतु विशाल जनसभा

आगामी 8 नवंबर, 2015 (रविवार) को प्रातः 10 बजे से मुख्य सभागार, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, में अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की उ. प्र. इकाई द्वारा पदोन्नति में आरक्षण हेतु एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। जनसभा को अन्य वरिष्ठ लोगों के अलावा परिसंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन, डॉ. उदित राज जी सम्बोधित करेगें।

उत्तर प्रदेश के साथियों से अपील है अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर जनसभा को सफल बनाएं।

–: निवेदक :–

जगजीवन प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष , मो . 09415007459,
धर्म सिंह, प्रधान महासिचव, उ.प्र., मो. 9415585545,
बी.डी. भारती, प्रदेश उपाध्यक्ष, मो. 9415021692,
के.पी. चौधरी, प्रदेश सचिव, मो. 7839318172

Census counts just 4% SC, ST families with a member in a govt job

Only about 4 per cent each of rural Scheduled Tribe and Scheduled Caste households have a member in a government job, according to the findings of the Socio Economic and Caste Census 2011 released earlier this month.

Of the country's rural ST population of 1.96 crore households, 8.60 lakh — or 4.37% — are in government jobs, as compared to 3.96 per cent (13 lakh of 3.3 crore) among the SCs. The STs represent 11 per cent of the base rural population of 17.91 crore households, the SCs 18 per cent.

Zonewise, North has the highest share among ST households with a government-salaried member, at 16 per cent. North Zone compris es J&K, Himachal Pradesh, Haryana and Punjab.

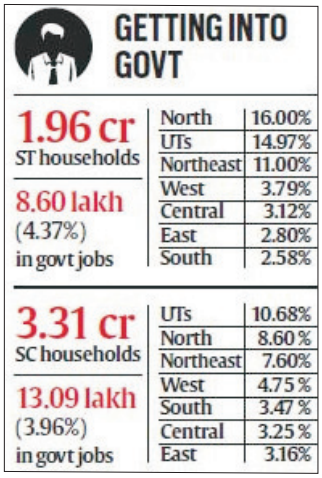

North is followed by the Union Territories at 14.97 per cent, the Northeast at 11 per cent, and West at 3.79 per cent. East has 2.80 per cent and South is at the bottom with 2.58 per cent. Surprisingly low in the list is Central Zone, which comprises states such as Madhya Pradesh and Chhattisgarh with a substantial tribal population. In this zone, only 3.12 per cent ST households have someone in a government job.

Among the Scheduled Castes, the zone with the highest proportion of households with a government employee is the Union Territories, which comprise the National Capital Territory of Delhi, Chandigarh, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli, Lakshadweep, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands.

The UTs with 10.68 per cent are followed by North Zone, Northeast, West, South and East (see graphic).

Rajasthan

Dalits and tribals in Rajasthan's villages follow a trend in keeping with the national one, despite over six decades of caste-based reservations. Rajasthan's 17.99 lakh ST households account for 17.64 per cent of the state's 1.02 crore households, and its 18.91 lakh rural SC households 18.51 per cent. A total 79,516 rural ST households, or 4.41 per cent, have a member in a government job. Among rural SC households, the count is 74,408, for 3.93 per cent.

As a proportion of the entire rural population in the state, ST households with a member in a government job account for only 0.78 per cent, while such SC households account for 0.73 per cent. The fact that the STs have a slightly higher representation could be attributed to the large number of Meena (ST) households sending members to government jobs.

-Mahim Pratap Singh
Jaipur

www.indianexpress.com

+++

J & K Confederation's Convention on 1st Nov.

JAMMU, 10 Oct. 2015

Sh. R. K. Kalsotra, President All India Confederation of SC/ST/OBC Organizations, J&K State apprised the media that today's press conference has been held to highlight the failure of the present Government to protect the constitutional rights of Reservation in Promotion of the SC/ST/OBC, RBA and LoC Category employees/Officers in the court of law. The judgment is likely to do irreparable financial and status loss to the reserved category officials in particular and the weaker sections in general as there is merely 2-3% reservation for the reserved category in government services. It is important to disclose that reservation in J&K started in 1970 for SC and 1991 for ST and OBC whereas it commenced in 1950 in the rest of the country. It is entirely the failure of the present government which could not defend its own Reservation Act 2004. Ever since the Constitutional amendment 77, 81, 82 and 85 have been made by the Parliament, we have been asking the state government from time to time to get the said amendments passed in state assembly, though the Reservation Act 2004 has been passed by the state assembly after the said amendments but the ruling class has always been ignoring the interest of the reserved categories.

The government is forcefully impressed upon to do everything for protection of the Constitutional rights of the reserved categories and in the meantime to ask the Law Department not to implement the Judgment dated 09-10-2015. The Reserved Category Ministers and MLA/MLCs and other legislatures are also requested to take up and pursue the matter with the Hon'ble Chief Minister and Deputy Chief Minister in whose tenure the Reservation Act of 2004 was passed. It is mentioned here that the Government data shows that there is inadequate representation of reserved categories in Govt. services as these categories are still educationally and economically backward. We are mobilizing the effected sections of the society and have called a One day biggest ever convention in Jammu on 1-11-2015 to educate the people about their bleak future. If government fails to protect our rights, we will expose the Government and gherao the Civil Secretariat on its opening in Jammu.

- Sh. R. K. Kalsotra
President, J&K Confederation
Mob.: 9419182452

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 18 ● Issue 22 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 October, 2015

Sample of the Handbill for the forthcoming Rally is being published. It is an earnest appeal to the Confederation Leaders that they should get it printed on behalf of State and District Units and distribute

Jai Bheem !

Dr. B. R. Ambedkar

Jai Bharat!!

Dr. Udit Raj,
National Chairman

All India Confederation of SC/ST Organisations Calls

A Rally of 10 Lakhs To Oppose Anti-Reservationists

Venue : Ramlila Ground, New Delhi

Date & Time : 7th Dec., 2015 at 10 AM

Friends,

Reservation has never been under attack as strongly as it is now. 5 lac Patels ,who are amongst the richest communities of the world, have come together and attacked reservation; they have demanded that either they be given reservation or reservation should be abolished. Various sections of society have demanded that reservations should be on economic basis. If SCs and STs sit quietly, then days are not far when it will be finished. Earlier people had this misconception that whosoever snatches reservations will have to pay a very heavy price for it; they should know that more than one-third of reserved posts have been abolished by stopping recruitments in class IV, introducing outsourcing and employing on contract basis. People are waiting for their battle to be fought by MPs, MLAs and other representatives. Employees and officer crib and curse saying that politicians should fight for our rights, they should resign – are the employees and officers not getting the benefit of reservation? Employees and officers can also fight against abolition of reservation and sacrifice their jobs for the cause. Both employees and politicians enjoy benefits of caste certificates and reservation. The All India Confederation of SC/ST Organisations was formed in 1997; we fought with this belief that employees should fight on their own, and not depend on politicians. Why should not the strength of employees and social activists be used for protecting rights and self – respect; politicians cant be asked to fight at gunpoint, so let us use our own strength. Politicians have to work at the dictate of their bosses – most parties are led by those of forward castes, and not much can be expected of them. Employees and social activists don't work under any pressure and nothing can affect their jobs. If they come together in lacs, then enormous pressure will be built and politicians will have to step forward to support our cause, and parties also cannot go against us. When the Confederation held a historic rally on 11th December, 2000 at Ramleela Maidan, New Delhi, 3 Constitutional Amendments were made. To give a fitting reply to the 5 lac rally by Patels, we must hold a rally with 10 lac people at Ramleela Maidan, New Delhi on 7th December.

In Uttar Pradesh, lakhs of employees have started getting demoted. The right to reservation in promotion was given by the 85th Constitutional Amendment. The second time, when we had to save reservation in promotions in 2006 in the Supreme Court, National ChairmanDr. Udit Raj personally approached the Minister of Social Justice, Law Minister and the DOPT Minister to ensure that private lawyers were engaged to fight the case in the Supreme Court. Due to Dr. Udit Raj's efforts, Advocates KK Parasaran, M. Mariarputnam and Subba Rao were appointed by the Government to fight the case at a cost of 40 lacs, after which we were able to save reservation in promotions in Supreme Court. Again on 4th January 2011, when the Lucknow High Court ended reservation in promotions, Dr. Udit Raj again tried to save it for the third time, the employees and officials there treated him like an untouchable and started doing demonstrations of their own accord. When he did not receive any support, he had to stay quiet, and these employees and officers are also responsible for demotions. They not only wasted their time and money in the wrong direction, but also gave a message to the Government that we have no unity amongst ourselves, which was not the case in 1997 when we fought against the Government orders which were destroying reservation. In the last 18 years, has any other SC/ST organisation other than the Confederation, fought and secured the rights? Reservation in Lokpal was given when we introduced the Bahujan Lokpal Bill. A Ministerial committee was formed in 2004 and an officers committee was made in 2006 and 2008 for consideration of reservation in private sector, but at that time, the Confederation did not receive desired support from our brethren, otherwise the situation would have been very different now. Sometimes, our people are carried away by emotion and caste and this is what happened. Earlier we were fighting for betterment, now we have to fight to save what we already have.

Several so – called Ambedkarites have not stopped attacking Dr. Udit Raj for joining the BJP. They should understand that he has raised the most number of issues related to the rights and exploitation of Dalits in Parliament, no other Member comes even close. Why don't they discuss which party was in power in Uttar Pradesh when the right to reservation in promotion was stopped? Now the only way is to fight together in lacs so we are able to save reservations. Every day attacks on Dalits are increasing. To fight this, we have to be united and there is no other way to empower ourself other than reservations. Has anyone stopped us from being a part of media, industries, share markets, higher education, armed forces etc.? Those who fight for reservation are told that they are fighting for the welfare of only a few people, why don't they fight for participation in other sectors as well. What has stopped such people to fight in other areas?

There is no sympathy for Dalits, Backwards or women that they can be empowered except unity and strength. Will the Government not be bound to pass the bill for reservation in promotion if 10 lac people gather at the Ramleela Maidan on 7th December 2015? The anti reservationists will not stand if we counter them with such strength. Please assemble in lacs at Ramleela Maidan, New Delhi on 7th December at 10 AM.

By

Jagjivan Prasad, Dharam Singh, Kidarnath (UP), Siddhartha Bhajane, Archana Bhoyar, Sanjay Kamble, Sanjay Adhangale, Siddhartha Kamble (Maharashtra), Mahasingh Bhurania, S. P. Jarawata (Haryana), Dharshan Singh Chanded, Tarsem Singh (Punjab), Brahm Prakash, Dr. Nahar Singh, Ravindra Singh, N. D. Ram, R. C. Mathuriya, Dr. Anju Kajal, Ramnandan Ram, R. S. Hans Karm Singh Karma, Dr. Dhananjay (Delhi), Moolaram, Vishram Meena, M.L. Rasu, Mukesh Meena (Rajasthan), Harishchand Arya, Heera Lal, Rohit Kumar, (U.K.), Mihir Sethi, Alekh Malik, D. K. Behera, Narayan Charan Das (Orissa), Param Hans Prasad, B. Bharati (M.P.), R. S. Maurya, Ramubhai Vaghela, N.J. Parmar, Yograj Vaghela (Gujarat), S. Karuppaiah, P. N. Perumal, G. Sriniwasan, M. Mathiparayanav (Tamilnadu), K. Ramankutty (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), K. Maheshwar Raj, K. B. Raju (Telangana), Dr. Shyam Prasad (A.P.), Anil Meshram, Harsh Meshram (Chhattisgarh), Kamal Krishna Mandal, Rameshwar Ram, Sapan Haldar, Vishwajit Shah, Manmohan Boral (W. Bengal), Madhusudan Kumar, Vinay Mundu (Jharkhand), R. K. Kalsotra (J & K), Madan Ram, Kumar Dhirendra, Shivdhan Paswan (Bihar), J. Shriniwaslu, Purushottam Das, Channappa (Karnataka), Sitaram Bansal (H.P.)

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya